

दिनांक: 11.07.2026

समय : 09:00 ए.एम.

आकाशवाणी जयपुर

प्रादेशिक समाचार

- भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए—प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को सम्बोधित करेंगे।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 12 सौ 58 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकर्पण करेंगे।
- विश्व जनसंख्या दिवस आज—प्रदेशभर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां।
- राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम में 12 सौ 58 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए छः विकास कार्यों का लोकार्पण, दस महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद—सरवाड़— केकड़ी—देवली फोरलेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबन्धु ने कल कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना के सभी काम निर्धारित समय—सीमा से पहले पूरे करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में हुई परियोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा मुआवजा संबंधी कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रगति पर हैं। नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि विभिन्न फीडर नहरों, पम्प हाउस, चंबल एक्वाडक्ट और अन्य घटकों पर कार्य जारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण—ट्राई के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत देश के 5 लाख 68 हजार से अधिक गांवों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क का ऐप आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण का काम एक लाख 40 हजार से अधिक ग्रामीण

शाखा डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। डाक सेवक अपनी नियमित डाक वितरण गतिविधियों के दौरान ट्राई द्वारा विकसित मोबाइल ऐप से नेटवर्क संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की कमियों की पहचान की जाएगी और नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किये जायेंगे।

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से इस अवसर पर विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में आज से सभी जिलों में 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि अभियान की थीम जब बच्चों में हो सही अन्तराल परिवार बने सही और खुशहाल पर ज़िले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है।

.....

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग-राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय, वैज्ञानिक और पारदर्शी है। आयोग ने आज जारी विज्ञप्ति में कहा कि सर्वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। केवल अधिकृत प्रगणक ही ओबीसी परिवारों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी दर्ज कर रहे हैं। आयोग के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक विकल्प आम लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से डेटा दर्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि अधिकृत प्रगणकों के लिए वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्था है। आयोग ने आमजन से सर्वे को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय रैंकिंग में सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक बूंदी दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा। एम-पैक्स श्रेणी में नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने पहला, बूंदी जिले की भीमा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दूसरा और घाट का बराना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह जानकारी सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार, डॉ. समित शर्मा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और एम-पैक्स मिलकर कार्य करें, ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है। उन्होंने सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान को देश में अग्रणी बनाने के लिए सभी संस्थाओं से समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।